आर.एन.आई. पंजीयन क्र. 39596/82 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)

साप्ताहिक

मालव अँचल

वर्ष 47 अंक 44 (प्रति रविवार) इंदौर, 21 जुलाई से 27 जुलाई 2024 पृष्ठ-8 मूल्य 3 रुपये

केंद्रीय बजट 2024

3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट 75 हजार हुई

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन के वादे को पूरा करता है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ।

युवाओं के लिए 5 नई योजनाओं का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

बिहार को विभिन्न योजनाओं के लिये बजट में 26000 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव।

आँध्रा को 15000 करोड़ मिलेंगे।

सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

एससी-एसटी और ओबीसी समाज के कल्याण के लिए और नई योजनाएं लाएगी सरकार।

10 हजार बायो फ्यूल प्लांट लगाए जाएंगे।

ये चीजें होंगी सस्ती

चमड़े के जूते, कपड़े, सोना-चांदी, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कैंसर दवा, प्लेटिनम, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स

इनके बढ़ेंगे दाम

सिगरेट, हवाई जहाज से यात्रा, प्लास्टिक का सामान, पेट्रोकेमिकल

रोजगार और स्किल के लिए 3 योजनाएं।

पहली नौकरी में एक महीने का भत्ता मिलेगा.एक लाख की सैलरी पर 3000 रुपये सरकार पीएफ में देगी।

बजट में गिनी-चुनी चीजें ही सस्ती या महंगी होती हैं। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में जीएसटी लागू किया था, जिसके बाद से बजट में केवल कस्टम और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई-घटाई जाती है। ड्यूटी के बढ़ने और घटने का का इनडायरेक्ट असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है। इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं।

एक साल में सिलेंडर 300 सस्ता, सोना-चांदी 13,000 रुपए महंगे

बीते एक साल में सोना-चांदी 13,000 रुपए महंगे हुए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 300 रुपए घटे हैं। इस दौरान तुअर दाल करीब 30 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। सोयाबीन तेल, आटा और चावल के दामों में ज्यादा बदलाव नहीं आया है।

बजट में इनडायरेक्ट टैक्स के बढ़ने घटने से सस्ते-महंगे होते प्रोडक्ट

प्रोडक्ट के सस्ते और महंगे होने को समझने के लिए सबसे पहले टैक्सेशन सिस्टम समझना होगा। टैक्सेशन को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बांटा गया है-

डायरेक्ट टैक्स

इसे लोगों की आय या मुनाफे पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स जैसे टैक्स इसमें आते हैं। डायरेक्ट टैक्स का बोझ वह व्यक्ति ही वहन करता है जिस पर टैक्स लगाया गया है और इसे किसी और को पास नहीं किया जा सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) इसे गवर्न करती है।

बड़े ऐलान

5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी।

इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।

रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी सरकार.

बिहार में 3 एक्सप्रेस वे का ऐलान।

बोधगया- वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा।

पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण।

बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल।

बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान।

छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन।

पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त पीएफ।

नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता।

इनडायरेक्ट टैक्स

इसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, वेट, सर्विस टैक्स जैसे टैक्स इसमें आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को एक व्यक्ति से दूसरे को शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे होलसेलर इसे रिटेलर्स को पास करता है, जो इसे ग्राहकों को पास कर देते हैं। यानी, इसका असर अंत में ग्राहकों पर ही पड़ता है। इस टैक्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) गवर्न करती है।

जीएसटी के दायरे में 90 प्रतिशत प्रोडक्ट, इससे जुड़े फैसले जीएसटी काउंसिल लेती है

2017 के बाद लगभग 90 प्रतिशत प्रोडक्ट्स की कीमत जीएसटी पर निर्भर करती है। जीएसटी से जुड़े सभी फैसले जीएसटी काउंसिल लेती है इसलिए बजट में इन प्रोडक्ट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होता है।

इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव से किसे कितना फायदा

वर्तमान में 10 लाख या उससे अधिक आय वाले लोगों पर 30 फीसदी का टैक्स लगाया जाता है, जो सरकार के खाते में जमा होता है। टैक्स स्लैब में नए प्रस्ताव के मुताबिक 18 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को इसमें शामिल करने की बात कही गई है, जिससे लोगों को 30 प्रतिशत टैक्स का भुगतान न करना पड़े। सवाल है कि आखिर टैक्स में बदलाव का प्रस्ताव क्यों दिया गया! दरअसल, लागत मुद्रास्फीति सूचकांक साल 2012-13 में 200 था, जो कि 2024-25 के लिए बढ़कर 363 तक पहुंच गया है। इन आंकड़ों में अंतर के लिए प्रमुख रूप से बढ़ती महंगाई भी जिम्मेदार है। इस वजह से पुराने टैक्स स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे बाजार संतुलन बना रहे।

वर्तमान में क्या है टैक्स स्लैब

2.5 लाख से 5 लाख रुपए की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लगता है। वहीं, 5 से 10 लाख रुपये की इनकम पर 20 प्रतिशत टैक्स लगता है। यदि किसी व्यक्ति की आय 10 लाख रुपये से अधिक होती है, तो उसे 30 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना होता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण केंद्रीय बजट मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। इस बार के केंद्रीय बजट में सरकार के पास वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कराधान (टैक्सेशन) के प्रावधानों में सुधार करने का मौका था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण के दौरान टैक्सेशन से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। हालांकि, उन्होंने करीब एक करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़े लाभ होने की बात कही। इस बार वित्त मंत्री ने नई कर प्रणाली में तीन से सात लाख रुपये तक 5 प्रतिशत कर का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि 3 रुपए तक की आमदनी पर करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना होगा। 7 से 10 लाख रुपये तक की आमदनी वालों के लिए 10 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार नए ऐलान से 4 करोड़ लोगों को नई कर प्रणाली में 17,500 रुपये तक का लाभ होगा।

आयकर लिमिट बढ़ी

अब जीरो से तीन लाख प्रति साल आय पर 0 फीसदी
3 से 7 लाख पर 5 फीसदी
7 से 10 फीसदी पर 10 फीसदी
10 से 12 लाख पर 15 फीसदी
12 से 15 लाख पर 20 फीसदी
15 लाख प्रति साल से अधिक पर 30 फीसदी टैक्स

संपादकीय

यूपी ने बजा दी भाजपा की पीपी

पहले कहावत थी कि - माया महा ठगिनी हम जानी अब कहा जाता है कि - सत्ता महा ठगिनी हम जानी । यूपी यानी हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश एक बार फिर महारथियों के गले की हड्डी कहिये या गले की फांस बन गया है। 2024 के आम चुनाव में इसी यूपी में चारों खाने चित हुई भाजपा की समझ में नहीं आ रहा है कि वो देश की सत्ता के इस प्रवेश द्वार का चौकीदार बदलें या रहने दें ? यूपी में आने वाले दिनों में एक साथ विधानसभा की 10 सीटों के उप चुनाव भी होना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नाथने के लिए मोशा की जोड़ी ने पिछले 7 साल में क्या कुछ नहीं किया। यूपी के एक राजपथ पर नमो ने मुख्यमंत्री योगी को सार्वजनिक रूप से अपनी जीप के पीछे कदमताल कराई थी। देश के इतिहास में देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री की ये पहली सार्वजनिक बेइज्जती थी ,लेकिन योगी जी योगी ठहरे। शिवभक्त हैं इसलिए अपमान का ये घूँट भी अमृत समझकर पी गए। बाद में मोशा की जोड़ी ने योगी जी को छकाने के लिए उनके दाएं-बाएं एक-एक उपमुख्यमंत्री नत्थी कर दिया लेकिन बात नहीं बनी। योगी को नाथने में मोशा कामयाब नहीं हुए। आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ नाथ सम्प्रदाय से आते हैं। उन्हें उनके गुरु ही नाथ पाए हैं ,दूसरा और कोई नही। लोकसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा का 400 पार का सुन्दर सपना टूटा तो योगी विरोधी एक बार योगी पर राशन-पानी लेकर पिल पड़े । बेचारे लखनऊ से दिल्ली की दौड़ लगा-लगाकर थक गए किन्तु योगी को मुख्यमंत्री पद से विदाई नहीं दिला पाए। योगी जी का सिंघासन हिला पाना उनके विरोधियों के लिए आसान नहीं है। आप इसे टेढ़ी खीर समझिये। योगी को सत्ताच्युत करने का मन मोशा की जोड़ी का भी है लेकिन वे साहस नहीं कर पारहे हैं। उन्हें पता है कि इस समय उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भाजपा का हिंदुत्ववादी एजेंडा चलाने वाला कोई दूसरा नेता भाजपा के पास नहीं है । कम से कम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तो कतई नहीं हैं। दूसरे उप मुख्यमंत्री की हैसियत भी योगी के मुकाबले शून्य है। दोनों उपमुख्यमंत्री लोकसभा चुनावों में अपने-अपने इलाकों में नाकाम साबित हो चुके हैं। भाजपा यदि जम्मू-कश्मीर के उप राज्य पाल मनोज सिन्हा को भी उत्तर प्रदेश में योगी का विकल्प नहीं बना सकती। भाजपा का ही नहीं बल्कि संघ का हाईकमान भी जानता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वैसे नहीं बदला जा सकता जैसे कि गुजरात में मुख्यमंत्रियों को बदला जाता है। यूपी, गुजरात नहीं है यूपी है। यहां गुजराती मॉडल कामयाब होने वाला नहीं है। दो दिन के लम्बे विचार विमर्श के बाद योगी जी के प्रमुख प्रतिद्वंदी उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य लखनऊ वापस लौटे लेकिन खाली हाथ। उन्हें मोशा की जोड़ी योगी को हटाने का आश्वासन नहीं दे पायी। दे भी नहीं सकती,क्योंकि योगी इस समय भाजपा की मजबूरी बन गए है। बिना योगी के यूपी में भाजपा को अपने पांव जमाये रखने में बहुत समस्या हो सकती है। मोशे की जोड़ी जानती है कि जिस तेजी से यूपी में भाजपा की मुट्ठी से जनसमर्थन बालू की तरह खिसक रहा है उसे देखते हुए नेतृत्व परिवर्तन का जोखिम नहीं लिया जा सकता। योगी आदित्यनाथ के पास सियासत करने के लिए अभी बहुत समय है। वे अभी कुल 52 के हुए है। योगी हवाई जहाज से राजनीति में नहीं उतरे । वे विधायक रहे ,फिर संसद बने और फिर मुख्यमंत्री। योगी ने सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का सम्पूर्णानन्द का कीर्तिमान भंग कर दिया है। वे 2017 से लगातार यूपी के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें भाजपा ने पहली बार अपनी जरूरत के हिसाब से और दूसरी बार मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाया था। अब भाजपा को ये तय करना है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली करारी हार के बावजूद योगी जी को आगे भी मुख्यमंत्री पद पर रखा जाये या नहीं ?

आपको ध्यान देना होगा कि योगी आदित्यनाथ भाजपा के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो संघ दीक्षित नहीं है । उन्होंने दीक्षा अपने चाचा महंत अवैद्यनाथ से ली थी। इसलिए योगी जी को न भाजपा नाथ पा रही है और न आरएसएस। वे सबसे अलग हैं। योगी चार बार के सांसद हैं। उनकी अपनी हिन्दू वाहिनी है जो बजरंग दल या विहिप जैसी नहीं है। यानि योगी भाजपा की कृपा से राजनीति में नहीं हैं । वे जिस पार्टी के मंच से राजनीति करेंगे अपना वजूद बनाये रखेंगे। योगी जी पिछले एक दशक में भी बदले नहीं है। वे पहले भी मुस्लिम विरोधी राजनीति करते थे और आज भी कर रहे हैं।

महानगरों में बढ़ता जानलेवा प्रदूषण गंभीर चुनौती

ललित गर्ग

चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी चर्चित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका लासेंट के हाल के अध्ययन में वायु प्रदूषण की बढ़ती विनाशकारी स्थितियों के आंकड़े न केवल चौंकाने वाले है बल्कि अत्यंत चिन्तातनक है। भारत के दस बड़े शहरों में हर दिन होने वाली मौतों में सात फीसदी से अधिक का मुख्य कारण हवा में व्याप्त प्रदूषण है। वहीं दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली में यह आंकड़ा साढ़े ग्यारह प्रतिशत है। भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण के रूप में पसर रही मौत के लिये सरकार एवं उनसे संबंधित एजेंसियों की लापरवाही एवं कोताही शर्मनाक है, क्योंकि सरकार द्वारा 131 शहरों को आवंटित धनराशि का महज 60 फीसदी ही खर्च किया जाता है। गंभीर से गंभीरतर होती वायु प्रदूषण की स्थितियों के बावजूद समस्या के समाधान में कोताही चिन्ता में डाल रही है एवं आम जनजीवन के स्वास्थ्य को चौपट कर रही है। महानगरों में प्रदूषण का ऐसा विकराल जाल है जिसमें मनुष्य सहित सारे जीव-जंतु फंसकर छटपटा रहे हैं, जीवन सांसों पर छाये संकट से जूझ रहे हैं।

केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण एवं हवा में घुलते जहरीले तत्वों की चुनौती के मुकाबले के लिये राष्ट्रीय वायु स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन की घोषणा 2019 में की थी। जिसका मकसद था कि खराब हवा के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभाव को कम किया जा सके। सरकार की कोशिश थी कि देश के चुनिंदा एक सौ तीस शहरों में वर्ष 2017 के मुकाबले वर्ष 2024 तक घातक धूल कणों की उपस्थिति को बीस से तीस फीसदी कम किया जा सके। लेकिन विडम्बना है कि तय लक्ष्य हासिल नहीं हो सके। महानगरों-नगरों को रहने लायक बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकारों की नहीं है, बल्कि हम सबकी है। हालांकि लोगों को सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी है, एंटीडस्ट अभियान को निरन्तर जीवन का हिस्सा बनाना होगा। लोगों को खुद भी पूरी सतर्कता बरतनी होगी। लोगों को खुली जगह में कूड़ा नहीं फैंकना चाहिए और न ही उसे जलाया जाए। वाहनों का प्रदूषण लेवल चैक करना चाहिए। कोशिश करें कि हम निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें और सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली पटाखे जलाने की भौतिकतावादी मानसिकता को विराम देना जरूरी है। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण की वैश्विक अभिधारणा को मूर्त रूप देने के लिये इको फ्रेंडली दीपावली मनाने की दिशा में गत दो-तीन साल में कई पायदान हम ऊपर चढ़े हैं, एक सकारात्मक वातावरण बना। लेकिन पटाखों से ज्यादा खतरनाक हैं पराली का प्रदूषण। पराली आज एक राजनीतिक प्रदूषण बन चुका है। दिल्ली एवं पंजाब में एक ही दल ही सरकारें है, दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय क्यों नहीं आम आदमी पार्टी की सरकार समाधान देती।

प्रदूषण से ठीक उसी प्रकार लड़ना होगा जैसे एक नन्हा-सा दीपक गहन अंधेरे से लड़ता है। छोटी औकात, पर अंधेरे को पास नहीं आने देता। क्षण-क्षण अग्नि-परीक्षा देता है। पर हां! अग्नि परीक्षा से कोई अपने शरीर पर फूस लपेट कर नहीं निकल सकता। इसके लिये शहरों में वृक्षारोपण करके हरियाली का दायरा बढ़ाना, कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन, इलेक्ट्रानिक वाहनों को प्रोत्साहन तथा इन वाहनों के लिये चार्जिंग स्टेशन बनाने जैसे प्रयास करने के सुझावों का क्रियान्वित करने की अपेक्षा है, इसके लिये जो कार्यक्रम प्रदूषण से ग्रस्त चुनिंदा शहरों में चलाया जाना था, लेकिन स्थानीय प्रशासन की तरफ से इस दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। जिससे समस्या उग्र से उग्रतर होती जा रही है। इसी कारण देश के अधिकांश शहर गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में हैं। लेकिन स्थानीय निकायों व प्रशासन ने संकट की गंभीरता को नहीं समझा। इस दिशा में अपेक्षित सक्रियता नजर नहीं आई। प्रश्न है कि पिछले कुछ सालों से लगातार इस महासंकट से जूझ रहे महानगरों को कोई समाधान की रोशनी क्यों नहीं मिलती? सरकारें एवं राजनेता एक दूसरे पर जिम्मेदारी ठहराने की बजाय समाधान के लिये तत्पर क्यों नहीं होते? प्रशासन अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रही है?

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये सक्रिय है, केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये करीब साढ़े दस हजार करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी। लेकिन विडम्बना है कि पर्याप्त फण्ड होने के बावजूद सिर्फ साठ फीसदी राशि ही इस मकसद के लिये खर्च की गई। वहीं सत्ताईस शहरों ने बजट का तीस फीसदी ही खर्च किया। कुछ शहरों ने तो इस मकसद के लिये आवंटित धन का बिल्कुल उपयोग नहीं किया। कैसे समस्या से मुक्ति मिलेगी? जीवाश्म ईंधन के उपयोग, सड़कों पर निरंतर बढ़ते पेट्रोल-डीजल वाहन, सार्वजनिक यातायात की बदहाली व कचरे का ठीक से निस्तारण न होने से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लक्ष्य हासिल करना जटिल होता जा रहा है। अब समस्या की विकरालता को देखते हुए केंद्र सरकार इस दिशा में नये सिरे से गंभीरता से पहल कर रही है, जिससे प्रदूषित शहरों को दी जाने वाली राशि का यथा समय अधिकतम उपयोग हो सके। पराली की समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1347 करोड़ रुपये और उपकरण दिए गए। अगर इस पर राजनीति करने की जगह ईमानदारी से काम होता तो प्रदूषण को कम करने की दिशा में हम कुछ कदम बढ़े होते।

वायु प्रदूषण एक जाना-पहचाना पर्यावरणीय स्वास्थ्य खतरा है।

हम जानते हैं कि हम क्या देख रहे हैं जब भूरे रंग की धुंध शहर के ऊपर छा जाती है, व्यस्त राजमार्ग पर धुआँ निकलता है या धुएँ के ढेर से धुआँ निकलता है। वायु प्रदूषण मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों स्रोतों से उत्पन्न खतरनाक पदार्थों का मिश्रण है। वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, घरों को वातानुकूलित करने के लिए ईंधन तेल और प्राकृतिक गैस, एसी का उपयोग, विनिर्माण और बिजली उत्पादन के उप-उत्पाद, विशेष रूप से कोयला-ईंधन वाले बिजली संयंत्र, और रासायनिक उत्पादन से निकलने वाले धुएं मानव निर्मित वायु प्रदूषण के प्राथमिक स्रोत हैं। बढ़ता प्रदूषण वैश्विक स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए एक बड़ा खतरा है। वायु प्रदूषण सभी रूपों में, हर साल दुनिया भर में 6.5 मिलियन से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है यह संख्या पिछले दो दशकों में बढ़ी है। भारत के महानगरों में यह अधिक विकराल होती जा रही है। उच्च वायु प्रदूषण से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं में कैंसर, हृदय रोग, श्वसन रोग, मधुमेह, मोटापा, तथा प्रजनन, तंत्रिका संबंधी और प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी विकार शामिल हैं।

वायु प्रदूषण बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से खतरनाक होने लगती है। महानगरों की हवा में उच्च सांद्रता है, जो बच्चों को सांस की बीमारी और हृदय रोगों की तरफ धकेल रही है। शोध एवं अध्ययन में यह भी पाया गया है कि दिल्ली जैसे महानगरों में रहने वाले 75.4 फीसदी बच्चों को घुटन महसूस होती है। 24.2 फीसदी बच्चों की आंखों में खुजली की शिकायत होती है। सर्दियों में बच्चों को खांसी की शिकायत भी होती है। बुजुर्गों का स्वास्थ्य तो बहुत ज्यादा प्रभावित होता ही है। हवा में कैडमियम और आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कैंसर, गुर्दे की समस्या और उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। 300 से अधिक एक्यूआइ वाले शहरों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी सहित अनेक महानगर क्षेत्र में रहने वाले सांस के रूप में जहर खींचने को क्यों विवश है, इसके कारणों पर इतनी बार चर्चा हो चुकी है कि उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं। निस्संदेह, राज्यों के शासन व स्थानीय प्रशासन के वायु प्रदूषण को लेकर उदासीन रवैये से नागरिकों के जीवन का संकट बरकरार है। सर्वविदित तथ्य है कि न तो सरकारों के पास पर्याप्त संसाधन हैं और न ही ऐसा विशिष्ट कार्यबल। नागरिकों की जागरूकता व जवाबदेही बढ़ाकर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस विषम एवं ज्वलंत समस्या से मुक्ति के लिये प्रशासन एवं सरकारों को संवेदनशील एवं अन्तर्दृष्टि-सम्पन्न बनना होगा।

नए स्वरूप में निर्मित आंनद मोहन माथुर सभागृह के उद्घाटन पर महापौर भार्गव ने कहा

मेरे गुरु के भी गुरु है वरिष्ठ अधिवक्ता और समाजसेवी आनंद मोहन माथुर

इंदौर। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाजसेवी आनंद मोहन माथुर की 97वी वर्षगाँठ पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बापट चौराहा स्थित आनंद मोहन माथुर सभागृह का उद्घाटन किया। इस मौके पर निगम सभापति मुन्नालाल यादव, वरिष्ठ डॉ. राजकुमार माथुर, आर्किटेक्ट पुनीत पांडे, अतुल सेठ, मुकुंद कुलकर्णी, डॉ. पूनम माथुर, प्रो. सरोज कुमार, कर्नल एनके माथुर विशेष रूप से उपस्थित थे।

अपने संबोधन में महापौर भार्गव ने कहा कि आनंद मोहन माथुर का व्यक्तित्व इतना बहुआयामी है कि उस पर बोलने के लिए एक दिन भी कम होगा। वे एक अधिवक्ता होने के साथ साथ समाजसेवी है और उन्होंने कई ऐसे ऐसे कार्य किये जो माइल्स्टोन है। वे मेरे गुरु एडवोकेट पीयूष माथुर के भी गुरु है। आज मेरा सौभाग्य है कि इस सभागार का उदघाटन मैं कर रहा हूं, जो एक नये स्वरूप में है। प्रो. सरोज कुमार ने कहा कि प्रदेश में केवल 2 अधिवक्ता हुए, जिन्होंने समाज हित में बड़ा दान दिया, उसमें से एक आनंद मोहन माथुर है। आर्किटेक्ट पुनीत पांडे ने कहा कि जब व्यक्ति अस्ताचल की ओर जाता है तो सूर्य पीछे आकर के परछाई को बड़ा कर देता है। माथुर साहेब उसका प्रमाण है। इस मौके पर केक काटकर माथुर साहेब का जन्मदिन भी मनाया जिसमें माथुर साहेब भी उपस्थित हुए। डॉ. राहुल माथुर ने आगे बताया कि सभागृह की आगामी तारीखों की भी बुकिंग आ रही है। सभागृह की गैलरी में भी दर्शको के लिए बैठक व्यवस्था की गई है। इस मौके पर शिक्षाविद् डॉ. निशा दुबे, वीना श्रीवास्तव, शोभा दुबे, आई ए एस पाल, ओमप्रकाश नरेडा, शफी शेख, प्रवीण जोशी, डॉ. रजनी भंडारी, मदन राणे, श्याम शर्मा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

स्टार्टअप ने तैयार किया अनोखा ड्रोन, सांसद लालवानी ने किया बीजारोपण

इंदौर। सांसद शंकर लालवानी अब ड्रोन की मदद ले रहे हैं। सांसद लालवानी ने विभिन्न क्षेत्रों में पीपल के बीजों का रोपण किया है। इंदौर के ड्रोन बनाने वाले स्टार्टअप पाइजर्व टेक्नोलॉजी ने अनोखा ड्रोन तैयार किया है। जिसकी मदद से लालवानी ने बीजों का रोपण किया। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत इंदौर ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कई इलाके ऐसे होते हैं जहां पर प्रत्यक्ष रूप से पेड़ लगाना संभव नहीं होता इसलिए इंदौर के स्टार्टअप के बारे में जब मुझे जानकारी मिली तो हमने पीपल के बीजों का रोपण ऐसी जगह पर किया जहां पेड़ लगाना एक मुश्किल काम है। सांसद ने कहा कि बारिश का मौसम बीजारोपण के लिए सबसे अनुकूल है और ज पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष माना गया है, इसलिए पीपल लगाने की कोशिश की गई है। पाइजर्व टेक्नोलॉजी के सीटीओ अभिषेक मिश्रा ने बताया की ड्रोन से सीधे बीजरोपण करने का प्रयोग भारत में पहली बार हुआ है। इससे पहले सीड बॉल गिराने के प्रयोग हुए हैं। साथ ही, ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया ड्रोन है और हमने उसे बीजारोपण के लिए अपग्रेड किया है।

सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि ड्रोन से बीज लगाने की तकनीक के माध्यम से इंदौर के आसपास कई क्षेत्रों को हरा-भरा किया जा सकता है और कृषि के क्षेत्र में भी इसकी अथाह संभावनाएं है।

साइबर क्रिमिनल्स ने अब अपनी फर्जी लिंक से

पार्सल मंगवाने वाले 4 आईफोन यूजर्स से 1.77 लाख रु. ठग लिए

चारों आईफोन वालों ने कोई न कोई पार्सल बुक करवाया था

इंदौर। साइबर क्रिमिनल्स ने अब अपनी फर्जी लिंक से आई-फोन यूजर्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। क्राइम ब्रांच को चार आई-फोन यूजर ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उनके मोबाइलों पर ऐसी लिंक भेजी जिसे डाउनलोड करते ही उनके मोबाइल का एक्सेस बदमाशों को मिल गया। उन्होंने चार लोगों से 1 लाख 77 हजार रुपए की धोखाधड़ी कर ली। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि चार शिकायतें मिली हैं। इन्हें ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले बदमाशों ने इंडिया पोस्ट के नाम से लिंक भेजी थी। लिंक ओपन करते ही इनका मोबाइल रिमोट एक्सिस एप्लिकेशन की तर्ज पर बदमाशों ने एक्सेस कर लिया। फिर बदमाशों ने आसानी से इनके ओटीपी और अन्य जानकारियां लेकर रातोरात इनके बैंक खातों से 1 लाख 77 हजार रुपए की राशि निकाल ली। आईफोन यूजर्स को लेकर ये पहली चार शिकायतें मिली हैं। जो लिंक बदमाशों ने भेजी थी, वह भी एपीके फाइल की थी। डाउनलोड होते ही उनका आईफोन मोबाइल भी बदमाशों ने एक्सिस कर लिया।

पता गलत है, ऐसा मैसेज भेजा था- फरियादी विनोद ने बताया कि मैसेज मिला था कि आपका पता सही नहीं है, आपका पार्सल वापस चला जाएगा। एड्रेस अपडेट करने के लिए 24 घंटे में इस लिंक को क्लिक कर डिटेल शेयर करें। लिंक क्लिक की तो खाते से 1 लाख 4 हजार रुपए निकल गए। मनदीप सिंह से 38 हजार, यतीश से 11,650, विश्वनाथ से 23,700 रु. की ठगी की गई है। इन सभी के कोई न कोई पार्सल आने वाले थे, इसलिए वे विश्वास में लिंक क्लिक कर गलती कर बैठे।

शहर में बढ़ाए जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन

वाहनों की बढ़ती संख्या के मध्य नजर की जा रही कोशिश

इंदौर। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों और सीएनजी वाहनों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर तो सरकार द्वारा सब्सिडी भी जा रही है। इसी कारण शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोगों का भी इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति रुझान बढ़ा है। हालांकि जिस तादाद में शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है, उस अनुसार चार्जिंग स्टेशनों की कमी है। शासन प्रशासन द्वारा चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने की भी लगातार कोशिश की जा रही है।

जानकारी अनुसार महानगर बनते इंदौर में दिन-प्रतिदिन इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है वायु प्रदूषण नहीं है। प्रदेश सरकार की ओर से इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है जिससे वायु प्रदूषण लगे और बड़े एक तरह से देखा जाए तो शहर में इलेक्ट्रिक बस चल रही है। इंदौर सिटी बस ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास लगभग 40 से अधिक बसें और और अभी और आ रही है। इसके अलावा देखा जाए तो ई-रिक्शा है स्कूटर है। कार है और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगभग साडे 7000 के आसपास है। इतनी तादाद होने के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए हैं और मात्र शहर में 150 का दावा किया जा रहा है। अभी भी कहा जा रहा है कि शहर में 40 साल भी जारी कर दिए गए हैं लेकिन कब बनेंगे कहां बनेंगे को लेकर तैयारियां की गई है। स्टेशनों का केवल दावा किया जा रहा है।शहर के मध्य से लेकर दूर-दराज तक अगर चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है तभी सही मायने में इलेक्ट्रिक वाहनों को फायदा मिलेगा। शहर में लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नगर निगम के पास ही अन्य कई बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन है उनका चार्जिंग स्टेशन भी बराबर नहीं है और अधिकारियों द्वारा केवल दावे किए जा रहे हैं कि चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं।

पेमेंट के लिए निगम अधिकारियों की ओर देख रहे ठेकेदार

सरकार से कम राशि आने का बहाना बनाकर फिर रोक रहे भुगतान

इंदौर। नगर निगम अधिकारियों ने एक बार फिर ठेकेदारों का भुगतान रोक दिया है। पेमेंट रोकने के कारण कई प्रोजेक्ट का काम भी ठेकेदारों ने धीमा कर दिया है। इससे शहर का विकास प्रभावित हो रहा है। पेमेंट रोकने के पीछे निगम अधिकारियों का तर्क है कि इस महीने सरकार से मिलने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि काम भेजी गई है। इस कारण निगम खजाने में धनराशि की कमी है। इसलिए बड़े ठेकेदारों का पेमेंट रोका गया है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब नगर निगम अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों का पेमेंट रोका गया हो इसके पहले भी कई महीनों तक लगातार ठेकेदार अपने किए गए कार्य के भुगतान के लिए निगम के चक्कर लगाने को मजबूर रहे हैं।

जानकारी अनुसार नगर निगम लंबे समय से आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। इस कारण शहर के विकास के कई प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं या शुरू ही नहीं हो सके हैं। हालांकि इसके बाद भी जनकार्य और अन्य विभाग लगातार टेंडर जारी कर रहे हैं, लेकिन भुगतान नहीं होने के कारण ठेकेदारों ने निगम प्रोजेक्ट में रुचि दिखाना काम कर दिया है। कहीं ठेकेदार तो अपना बकाया भुगतान लेने के बाद अब निगम से दूरी बना चुके हैं। वहीं कुछ ऐसे भी ठेकेदार हैं जो निगम के प्रोजेक्ट धीमी गति से चला रहे हैं। कार्य करने के बाद पहले किए गए कार्य का भुगतान लेने की कोशिश करते हैं और पेमेंट होने के बाद ही प्रोजेक्ट को आगे चलते हैं। निगम द्वारा ठेकेदारों को पेमेंट नहीं करने के चलते हालात यह है कि जहां पहले एक टेंडर जारी करने के बाद ठेकेदारों में काम्पिटीशन होती थी वहीं अब एक टेंडर के लिए कई-कई बार विज्ञप्ति जारी करना पड़ रही है।

ठेकेदार बना रहे निगम से दूरी, नहीं दिख रहे कार्यों में रुचि-कार्य समय पर करने के बाद भी निगम द्वारा जब भुगतान करने में देरी की जा रही है तो ठेकेदारों ने निगम से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। वर्तमान में भी ठेकेदार अपने पेमेंट के लिए नगर निगम के चक्कर काटने को मजबूर हैं। दिन में कई बार देखा जा सकता है जब निगम के गलियारों में ठेकेदारों की भीड़ देखी जा सकती है।

लाड़ली बहनों को 1250 के अतिरिक्त अगस्त में मिलेंगे 250 रुपए

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को किया संबोधित, दी बहनों को सौगात

मंत्री सावन में अपने क्षेत्र की लाड़ली बहनों से राखी बंधवाकर मनाएं रक्षाबंधन

श्रावण मास में श्रद्धालुओं के आवागमन और कानून व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में सावन माह का विशेष महत्व है। सावन माह में प्रत्येक लाड़ली बहन के खाते में आने वाली एक तारीख को 250 रुपए अंतरित किए जाएंगे, यह राशि प्रतिमाह जारी होने वाली 1250 रुपए की राशि के अतिरिक्त होगी। लाड़ली बहनों को प्रतिमाह जारी होने वाले 1250 रुपए पूर्वानुसार उनके खाते में जारी किए जाएंगे। उन्होंने मंत्रीगण से रक्षाबंधन के पर्व पर अपने-अपने क्षेत्र की लाड़ली बहनों से राखी बंधवाने का आहवान भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में यह बात कही।

गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को गुरु परंपरा से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय परंपरा से जुड़े त्योहारों को मनाने का आनंद ही अलग है। इस क्रम में गुरु पूर्णिमा पर स्कूल शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों में गुरुओं के सम्मान के लिए आयोजित कार्यक्रम से प्रदेशवासियों को गुरु परंपरा से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारतीय त्यौहार परंपरा सामाजिक उद्देश्यों से जुड़ी है। संक्रांति का पर्व नारी सशक्तिकरण और गुड़ी पड़वा को विक्रमोत्सव के रूप में मनाया गया है। इसी क्रम में सावन मास को बहनों के त्यौहार के रूप में मनाया जाएगा। यह गतिविधियां भारतीय संस्कृति के अनुसार त्यौहार मनाने की परंपरा को बनाए रखने में सहायक होंगी।

श्रावण मास में मंदिरों में बढ़ रहा है श्रद्धालुओं का आवागमन-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्रावण मास में मंदिरों में श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ रहा है। सभी मंत्री अपने-अपने क्षेत्र में भक्तों के आवागमन, कानून-व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दें। साथ ही वर्षा काल चलने के कारण नदी व बांधों में बढ़ रहे जल स्तर के संबंध में भी जिला प्रशासन के सतत संपर्क में रहते हुए जागरूक रहे।

औद्योगिक गतिविधियों और निवेश का परिणाममूलक वातावरण हुआ निर्मित-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जबलपुर में हुई रीजनल इंडस्ट्री कान्क्लेव की सफलता के लिए मंत्रि-परिषद के सभी सदस्यों को बधाई दी। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि जबलपुर कॉन्क्लेव के सुखद परिणाम सामने आए हैं। निवेशक के साथ हुई सकारात्मक चर्चा से महाकौशल क्षेत्र तथा प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों और निवेश का परिणाममूलक वातावरण निर्मित करने में सफलता मिली है।

दलहन उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेखित मध्यप्रदेश से संबंधित बिंदुओं की चर्चा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश वर्ष 2023-24 में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी से आगे बढ़ते राज्यों में शामिल है। मध्यप्रदेश ने 15 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की है। केंद्रीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में मध्यप्रदेश से जुड़े दो नदी जोड़ो अभियानों केन-बेतवा लिंक परियोजना और काली सिंध-चंबल-पार्वती लिंक परियोजना का भी उल्लेख किया है। दलहन उत्पादन में मध्यप्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है और तिलहन उत्पादन में देश में नंबर दो पर है।

प्रदेश में प्रौद्योगिकी के आधार पर उपज अनुमान का हुआ सफलतापूर्वक परीक्षण-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश देश में दलहन का एक चौथाई हिस्सा उत्पादन कर रहा है और देश के तिलहन उत्पादन में मध्यप्रदेश का पांचवा हिस्सा है। सोयाबीन उत्पादन में मध्यप्रदेश पुनः प्रथम स्थान पर है। चना व गेहूं के उत्पादन में भी मध्यप्रदेश प्रथम है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में मध्यप्रदेश, देश में द्वितीय स्थान पर है। मक्का, मोटे अनाज, मूंगफली और मटर के उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। इस उपलब्धि के लिए सभी किसान भाई बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के आधार पर उपज अनुमान का मध्यप्रदेश में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसके लिए भी प्रदेश को केंद्र शासन द्वारा बधाई दी गई है।

धार जिले में 4 हजार 445 करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट प्रस्तावित-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देश के 7 पीएम मित्र पार्क में से एक धार जिले में 4 हजार 445 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इससे लगभग 1 लाख स्थानीय जनजातीय युवाओं को लाभ मिलेगा। राज्यों के शिक्षण अधिगम को सुगम बनाने के लिए मध्यप्रदेश ने 6 में से 6 अंक अर्जित किए हैं। एकल राज्य अधिनियम के अंतर्गत पंचायती सहकारी समितियों की संख्या में मध्यप्रदेश देश में चौथे स्थान पर आया है। सीमेंट उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में पांचवें स्थान पर है। इंदौर बायो सीएनजी प्लांट का आर्थिक सर्वेक्षण में केस स्टडी के रूप में उल्लेख हुआ है। आर्थिक सर्वे में भावांतर भुगतान किसान हितैषी ढांचे के रूप में चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश के इतने बिंदुओं का उल्लेख होना हम सबके लिए प्रसन्नता और गर्व का विषय है।

संविदा कर्मियों के मानदेय में 3.87 फीसदी की वृद्धि, ढाई लाख अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

भोपाल। मध्य प्रदेश के करीब ढाई लाख संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों का मानदेय एक अप्रैल 2024 से 700 रुपये से लेकर ढाई हजार रुपये तक बढ़ जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर सरकार ने संविदा कर्मचारियों को 3.85 प्रतिशत की वृद्धि दर से वार्षिक वृद्धि देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में प्रावधान भी रखा गया है। संविदा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि देने का प्रावधान है।

मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी-अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि वित्त विभाग ने वर्ष 2023 में संविदा नीति जारी की है, जिसमें यह तय किया गया है कि हर साल एक अप्रैल को संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों की महंगाई दर (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) में वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया है, लेकिन राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों के मानदेय में 3.87 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे इनके पारिश्रमिक में 785 से 2535 रुपये प्रतिमाह का लाभ देखने को मिलेगा। आदेश एक अप्रैल 2024 से लागू माना जाएगा। फिलहाल, तीन माह का एरियर दिया जाएगा या नहीं आदेश में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। दरअसल, सरकार ने अप्रैल में सीपीआई इंडेक्स दर जारी नहीं की थी, लेकिन जब महासंघ ने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपा एवं आंदोलन की चेतावनी दी, तब वित्त विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। इससे संविदा कर्मचारियों को फायदा तो होगा, पर उतना नहीं होगा, जितना अन्य राज्यों के संविदा कर्मचारियों को मिलेगा।

हालांकि, संविदा कर्मचारी-अधिकारी महासंघ ने इस सीपीआई इंडेक्स दर पर आपत्ति जताई है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा कि भारत सरकार ने 5.39 प्रतिशत का सीपीआई इंडेक्स जारी किया है, यहां भी वही जारी किया जाना था। वहीं नियमित कर्मचारियों के समान तीन प्रतिशत इंक्रीमेंट भी देना था। मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर कहेंगे कि संविदा कर्मचारी कोई मजदूर नहीं है, जो सीपीआई इंडेक्स दिया जा रहा है। इसे समाप्त कर पहले की तरह महंगाई भत्ता ही दिया जाए।

मॉरीशस में महकेगा 'विश्वरंग' भारत सहित 35 देश करेंगे मंथन

भोपाल। साहित्य-संस्कृति और कला के इन्द्रधनुषी रंगों से सराबोर एशिया का सबसे विराट महोत्सव 'विश्वरंग' शीघ्र ही अपना छटवाँ सोपान मॉरीशस में पूरा करने जा रहा है। आगामी 7,8 और 9 अगस्त को भारत सहित दुनिया के पैंतीस से भी ज़्यादा देश हिन्दी का परचम लहराने विश्वमंच पर एक साथ होंगे। रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के साथ विश्वरंग की मुख्य मेजबानी मॉरीशस स्थित विश्व हिन्दी सचिवालय अपने सहयोगी संस्थानों के संयुक्त संयोजन में करेगा। तीन दिनों की बहुरंगी गतिविधियों के साक्षी बनने मॉरीशस गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन, प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगनोथ, उप प्रधानमंत्री लीला देवी दुकन, विश्व हिन्दी सचिवालय की महासचिव डॉ. माधुरी रामधारी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे और मॉरीशस उच्चायुक्त नंदिनी के. सिंगला सहित प्रतिभागी देशों की गणमान्य विभूतियों को आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर मॉरीशस स्थित रबीन्द्रनाथ टैगोर संस्थान के मुक्ताकाश परिसर में टैगोर की सात फीट ऊँची प्रतिभा का अनावरण 'विश्वरंग' के सौजन्य से किया जाएगा।

प्रदेश के ग्रामों को पूरे देश में आदर्श बनाने के लिए अभिनव प्रयासों को करें विस्तारित : उप-मुख्यमंत्री शुक्ल

आत्मनिर्भर पंचायत–समृद्ध मध्यप्रदेश संगोष्ठी में शामिल हुए

भोपाल। *उप-मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में आत्मनिर्भर पंचायत- समृद्ध मध्यप्रदेश की तीन दिवसीय संगोष्ठी के दूसरे दिन संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश को समृद्ध बनाना है तो पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि अमृतकाल में भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनायेंगे।*

केंद्रीय बजट में ग्रामीण विकास के प्रावधान में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए सतत प्रावधान किए जा रहे हैं। आज सिंचाई के रक़बे में निरंतर वृद्धि हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल-जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल पहुँचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, ग्रामीण सड़क योजना, आजीविका मिशन आदि के माध्यम से ग्रामीण जीवन को सहज और सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं का उचित लाभ सुनिश्चित करने और हर पात्र को लाभान्वित करने के लिए मैदानी अमले का प्रशिक्षित होना, आपसी समन्वय होना आवश्यक है। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि संकल्प और समर्पण से ग्रामीण विकास का नया अध्याय लिख सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त करने के प्रयास किए जा रहें हैं। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में सामुदायिक केंद्रों में ज़िला चिकित्सालय स्तर की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में दृढ़ इच्छाशक्ति से ग्रामीण सेवाओं को सशक्त करने के लिए समस्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी है, बिजली है, पानी है। आज हम तेज़ गति से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हमें अपनी क्षमता का उन्नयन कर दृढ़ इच्छाशक्ति से प्रयास करने होंगे। हमें नवाचारों को, अभिनव प्रयासों को पूरे प्रदेश में विस्तारित करना होगा, ताकि मध्यप्रदेश का ग्रामीण विकास पूरे देश में मॉडल बनें। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने आत्मनिर्भर पंचायत- समृद्ध मध्यप्रदेश संगोष्ठी में त्रि-स्तरीय पंचायत के सदस्यों और विशेषज्ञों की सहभागिता, उत्कृष्ट प्रयासों के साझाकरण के अभिनव प्रयास की सराहना की और सफलता की शुभकामनाएँ दीं।

उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने रीवा ज़िले में गौ-वंश संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने गौ-शाला को आत्मनिर्भर एवं रोज़गारों के सृजन का केंद्र बनाने के प्रयासों को साझा किया। साथ ही गौ-शालाओं से संबंधित शासकीय योजनाओं में प्रावधानों को सशक्त बनाने के लिए अनुभव आधारित सुझाव दिये। संगोष्ठी में गौ-वंश संरक्षण के लिए बसामन मामा गौ-वंश वन्य विहार रीवा की संकल्पना, व्यवस्था और कार्यान्वयन पर आधारित फ़िल्म का प्रदर्शन किया गया। एसीएस श्री श्रीवास्तव ने तीन दिवसीय संगोष्ठी में विभिन्न विषयों और अब तक हुई गतिविधियों की विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।

हर पंचायत में सामुदायिक भवन और हर पंचायत का अपना भवन होगा : मंत्री प्रह्लाद पटेल

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने पंचायत प्रतिनिधियों का आव्हान किया है कि वे पूरी लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करें। अधिकार तो स्वाभाविक रूप से मिल जायेंगे।

श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार पूरे प्रयास कर रही है कि हर पंचायत में सामुदायिक भवन हो और हर पंचापयत का अपना भवन हो। उन्होने कहा कि हर पंचायत अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की प्लानिंग क्षमता और समझदारी से कर सकती है। उन्होने कहा कि पंचायत राज एक साथ मिलकर जनकल्याण के लिये कार्य करने की भावना है। उन्होने कहा कि जनपद पंचायत उपाध्यक्षों की सहमति के लिये अनिवार्य रूप से उन्हें नस्ती भेजने संबंधी आदेश जल्दी ही जारी कर दिये जायेंगे। श्री पटेल आज यहां आत्मनिर्भर पंचायत- समृद्ध मध्यप्रदेश विषय पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और जीआईजेड द्वारा आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होने जनपद पंचायत, उपाध्यक्षों से आग्रह किया वे ऐसे कार्यों और गतिविधियों की सूची बना लें जिनमें वे समझते हैं कि उनका मत और सहमति आवश्यक हो। उन्होने कहा कि पंचायतों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिये उनके आंतरिक प्रशासनिक तंत्र को मजबूत बनाने की कार्रवाई चल रही है। निचले स्तर पर प्रशासनिक तंत्र की मजबूती आवश्यक है। श्री पटेल ने कहा कि विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध बजट राशि और वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। उन्होने कहा कि अंतिम उददेश्य लोगों को खुश करना और उनकी भलाई करना है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने बताया पर्यटकों को प्रदेश की समृद्ध ग्रामीण संस्कृति से परिचित कराने के लिये ग्रामीण पर्यटन योजना में पर्यटन के माध्यम से गांवों की आय बढाने के लिये 117 गांवों में होम स्टे निर्माण किया जायेगा। सरकार द्वारा 1000 होमस्टे बनाने का लक्ष्य है। इसके लिये जनजातीय क्षेत्रों में 60 प्रतिशत और गैर, जनजातीय क्षेत्रों में 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा। पर्यटकों को ग्राम भ्रमण, ग्रामीण खेल, आरामदायक स्टे, स्थानीय भोजन, लोक कला और हस्तशिल्प से परिचित कराया जायेगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल के मार्गदर्शन पर स्थानीय युवकों को आनलाइन पर्यटन गाइड का प्रशिक्षण दिलाया जायेगा।

कार्यशाला में गोवंशों का संरक्षण और संवर्धन, डिजी लाकर, जल गंगा संवर्धन अभियान, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पर विस्तार से जानकारी दी गई।

छात्र-परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए स्कूल शिक्षा मंत्री सिंह

भोपाल। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति-2020 का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षा को रोजगार से जोड़ने का कार्य प्राथमिक स्तर पर किया जा रहा है। विद्यार्थी क्षमता अनुसार विषय चुन सकें और अपनी रूचि के अनुसार सही केरियर का चयन कर सकें, इसके लिये स्कूलों में विषय विशेषज्ञों के माध्यम से काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह आज भोपाल के देहली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) में नवगठित छात्र-परिषद के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह ने कहा कि सही मायनों में शिक्षा का अर्थ अपने ज्ञान का दूसरों की भलाई में उपयोग करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र को स्कूल का आदर्श वाक्य स्वयं से पहले सेवा को आत्मसात करना चाहिए। कार्यक्रम को शिक्षण संस्थान के प्रो-वाईस चेयरमेन श्री हरि मोहन गुप्ता एवं अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। नवगठित छात्र-परिषद को मुख्य अतिथि ने शपथ दिलाई। इस मौके पर स्कूल के छात्रों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक नृत्य और गायन की प्रस्तुति दी गई। डीपीएस में आयोजित यह अलंकरण समारोह समग्र विकास को बढ़ावा देने और अपने छात्रों के बीच नेतृत्व के मूल्यों को स्थापित करने की स्कूल की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण था। यह एक महत्वपूर्ण अवसर था जो कार्यक्रम में उपस्थितजनों के लिये सदैव अंकित रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिये प्रेरक बनेगा।

मंत्रालय में आयुष विभाग की समीक्षा बैठक हुई

सिकल सेल एनीमिया रोग के उन्मूलन के लिए संवेदनशील क्रियान्वयन की आवश्यकता : आयुष मंत्री परमार

भोपाल। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने मंत्रालय स्थित प्रतिकक्ष में आयुष विभाग की समीक्षा की। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए कृत कार्यों एवं आगामी कार्ययोजना पर व्यापक चर्चा हुई। मंत्री श्री परमार ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया रोग के उन्मूलन के लिए मानवीय संवेदना के भावानुरूप दृष्टिकोण स्थापित कर कार्य करने की आवश्यकता है। सिकल सेल एनीमिया रोग, जनजागृति का विषय है और इसके नियंत्रण एवं उन्मूलन के लिए समर्पित तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। श्री परमार ने कहा कि लक्ष्य निर्धारित कर प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में सामाजिक अभियान के रूप में दृढ़ता से क्रियान्वयन किया जाए। इसके लिए शिक्षा क्षेत्र में स्वास्थ्य जागरूकता को अभियान बनाया जाना आवश्यक है। आयुष मंत्री श्री परमार ने प्रदेश के 89 जनजातीय बाहुल्य विकासखंडों में प्रभावित विकासखंडों का चिन्हांकन कर, वहां आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से सतत् जांच, निगरानी एवं जागरूकता के लिए क्रियाशील व्यवस्था बनाने और इसके क्रियान्वयन की निगरानी विभागीय अधिकारियों द्वारा किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे समस्त आयुष औषधालयों में आयुष चिकित्सकों, औषधि एवं आवश्यक संसाधन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। श्री परमार ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि प्रभावी क्षेत्र में स्कूल स्तर पर बच्चों में सिकल सेल एनीमिया को लेकर जागरूकता लाने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाएं और योजनाबद्ध रूप से सतत् जांच एवं निगरानी की जाए। श्री परमार ने परंपरागत वैद्यों के अनुभवों के लाभ लेने के लिए उनसे समन्वय बनाने और आवश्यकता अनुरूप तकनीकी का उपयोग करने को भी कहा।

जान्हवी कपूर की अजीबोगरीब ब्लेजर ड्रेस देख फैंस को याद आई उर्फी जावेद

पिछले हफ्ते से बॉलीवुड अदाकारा जान्हवी कपूर बाकी फिल्म बिरादरी के साथ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के जश्न में बिजी थीं। जान्हवी कपूर और उनके बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया शादी से पहले के समारोहों से लेकर बारात तक और फिर वेडिंग रिसेप्शन तक हर सेरेमनी का हिस्सा रहे। खैर, अब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के इवेंट खत्म हो गए हैं और सेलिब्रिटीज भी अपने काम पर वापस लौट गए हैं। इसी कड़ी में एक्ट्रेस जान्हवी कपूर भी अपने काम पर लौट गई हैं। उन्हें हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म उलझ के ट्रेलर लॉन्च पर स्पॉट किया गया, लेकिन वह ट्रोल हो गईं। एक एक्टर होने के अलावा

जान्हवी कपूर एक स्टाइल आइकन भी हैं। दरअसल, जान्हवी कपूर ने इस ट्रेलर लॉन्च के लिए ब्लैक एंड व्हाइट कलर की ड्रेस चुनी, जो काफी अजीब थी. ब्लेजर के लुक वाली यह ड्रेस काफी अटपटी थी। हालांकि, इस अटपटी ड्रेस में जान्हवी कपूर अपने स्टाइल का जलवा बिखेरने में कामयाब रहीं। इस अजीब, लेकिन काफी स्टाइलिश ट्यूब ड्रेस के साथ जान्हवी कपूर ने शूज पहने थे। नैचुरल मेकअप, सनग्लासेस और खुले बालों के साथ जान्हवी कपूर ने अपने लुक को पूरा किया। हालांकि, जान्हवी कपूर की इस ड्रेस को देखने के बाद फैन्स उनकी पोस्ट पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को इस ड्रेस को देखने के बाद उर्फी जावेद की याद आ रही है।

विक्की कौशल ने पत्नी कैटरीना के जन्मदिन पर शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री कैटरीना कैफ आज अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं। इस खास मौके पर उनके पति विक्की कौशल ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया है। विक्की ने कैटरीना के साथ अपनी कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, तुम्हारे साथ यादें सजोना मेरी जिंदगी का पसंदीदा काम है। हैप्पी बर्थडे माई लव। विक्की के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। फैंस इस कपल की केमिस्ट्री को देखकर काफी खुश हैं। विक्की और कैटरीना की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। कैटरीना कैफ बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं।

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक है। दोनों ने साल 2021 में शादी की थी। शादी के बाद से दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। विक्की के पोस्ट पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं। फैंस इस कपल को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और उनकी जोड़ी को हमेशा खुश रहने की दुआएं दे रहे हैं। विक्की और कैटरीना की जोड़ी बॉलीवुड में एक मिसाल है। दोनों एक-दूसरे के लिए कितना प्यार करते हैं, यह उनके सोशल मीडिया पोस्ट से साफ झलकता है।

मेलबर्न के भारतीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट हुई- नितांशी गोयल

पता लेडीज फेम नितांशी गोयल को मेलबर्न के भारतीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया है। इस साल की शुरुआत में जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तब एक्ट्रेस की उम्र महज 16 साल थी। इस छोटी सी उम्र में उन्हें अपने शानदार परफॉर्मेंस के लिए खूब तारीफें मिली थीं। अपने इस बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन के साथ ही नितांशी गोयल ने कई बॉलीवुड हसीनाओं को पछाड़ते हुए हिंदी फिल्मों की सबसे कम उम्र की एक्ट्रेस के रूप में बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट होने का नया रिकॉर्ड बना लिया है।

नितांशी गोयल की उम्र अब 17 साल हैं और इस उम्र में नॉमिनेशनल हासिल करने के साथ ही वह सबसे कम उम्र में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशनल हासिल करने वाली कुछ खास एक्ट्रेस की फेहरिस्त में शामिल हो गई हैं। इस लिस्ट में डिंपल कपाड़िया का नाम सबसे पहले आता है, जिन्हें 1973 में आई डेब्यू फिल्म बॉबी के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड का नॉमिनेशन मिला था।

आलिया-दीपिका-करीना को इस मामले में पछाड़ा

सायरा बानो को फिल्म जिस देश में गंगा रहता है के लिए जब फिल्मफेयर ने बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया था तो उनकी उम्र 17 साल थी। डिंपल कपाड़िया और सायरा बानो के अलावा और भी कुछ एक्ट्रेस ने कम उम्र में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशनल हासिल किया था।

बता दें कि नितांशी गोयल ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत 2012 में आई विक्की डोनर के साथ की थी। इसके बाद वह एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी, इंदू सरकार जैसी फिल्मों में नजर आईं।

एम्बर गर्ल्स स्कूल के अगले चैप्टर में दोगुना मज़ा लें, क्योंकि अमेज़न मिनीटीवी ने पसंदीदा टीन ड्रामा के दूसरे सीजन का रोमांचक ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है

एम्बर गर्ल्स स्कूल के हॉल में फिर से जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अमेज़न की मुफ्त वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा अमेज़न मिनीटीवी ने इस नए युग के टीन ड्रामा के बहुप्रतीक्षित दूसरे सीज़न की घोषणा की है। अपने डेब्यू सीजन की जोरदार सफलता के बाद, स्ट्रीमिंग सर्विस ने आज आगामी सीजन के लिए एक रोमांचक ट्रेलर का अनावरण किया, जो एम्बर गर्ल्स स्कूल में ओजस के जीवन और उसकी आगे बढ़ती यात्रा की एक झलक पेश करता है। रिलायंस एंटरटेनमेंट स्टूडियो द्वारा निर्मित और राजलक्ष्मी रतन सेठ द्वारा निर्देशित, एम्बर गर्ल्स स्कूल सीजन 2 में प्रिय कास्ट की वापसी होती है, जिसमें सेलेस्टी बैरागी, काजोल चुग, अद्रिजा सिन्हा, इशिका गगनेजा, हर्ष खुराना और श्रुति पनवार शामिल हैं।

एम्बर गर्ल्स स्कूल के नए सीजन में ओजस और उसके दोस्तों के साथ किशोरावस्था की जटिलताओं से निपटने के लिए एक अविस्मरणीय यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। आगामी सीजन 26 जुलाई से अमेज़न मिनीटीवी पर विशेष रूप से स्ट्रीम होगा, जो अमेज़न शॉपिंग ऐप, फायर टीवी, और प्ले स्टोर पर मुफ्त में उपलब्ध होगा। ट्रेलर हमें ओजस की दुनिया की एक झलक देता है, जहाँ वह कई चीजों को संभालने की कोशिश कर रही है - वह हेड गर्ल बनना चाहती है, एक बॉयफ्रेंड चाहती है, अपने तनावपूर्ण दोस्ती को सुधारना चाहती है, और स्कूल अधिकारियों के खिलाफ बगावत करना चाहती है। वह महसूस करती है कि उसे अधिक आत्मविश्वासी बनना है और हाँ-हाँ मिलाने वाली लड़की बनने की बजाय अपने पैरों पर खड़ा होना है। जो चीज वास्तव में उसके लिए मायने रखती है, वह है दोस्तों और परिवार के साथ रिश्ते को बनाए रखना, आशावादी रहना, और सबसे बढ़कर, खुद के प्रति सच्चे रहना। अपने विचार साझा करते हुए, अमेज़न मिनीटीवी के कंटेंट हेड, अमोघ दुसाद ने कहा, ÷हम अमेज़न मिनीटीवी पर एम्बर गर्ल्स स्कूल को एक और सीजन के लिए वापस लाने के लिए उत्साहित हैं। दूसरा सीजन स्कूल की बदलती गतिशीलता और ओजस की यात्रा की अंतर्दृष्टि को प्रदर्शित करेगा। दोस्ती, सहनशीलता और आत्म-खोज जैसे सार्वभौमिक विषयों के साथ, यह सीजन दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ने का वादा करता है। ओजस्वी की भूमिका निभाने वाली सेलेस्टी बैरागी ने नए सीजन के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा, मैं एम्बर गर्ल्स स्कूल सीजन 2 में ओजस की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए रोमांचित हूं।

मानसून के कारण हो गए हैं स्किन रैशेज तो यह घरेलू

उपाय आएगा काम

त्वचा की देखभाल करना हम सभी को बेहद पसंद होता है और इसके लिए आपको मार्केट में कई प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। वहीं मौसम भी बदल गया है और बरसात का सीजन शुरू हो चुका है। अक्सर बरसात के मौसम में हवा में मॉइस्चर बढ़ जाता है और ऐसे ही त्वचा में भी मॉइस्चर काफी बढ़ने लगता है, जिसके कारण त्वचा में खारिश होने लगती है और स्किन इन्फेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। स्किन रैश को ठीक करने के लिए वैसे तो मार्केट में आपको कई तरह के प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन इन प्रोडक्ट्स में मौजूद केमिकल आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा, जिसकी मदद से आप आसानी से त्वचा में होने वाले रैश को ठीक कर सकती हैं।

स्किन रैशेज के लिए क्या करें ?

एलोवेरा जेल
मुल्तानी मिट्टी
विटामिन-ई कैप्सूल

स्किन रैशेज को कम करने के लिए एलोवेरा जेल के फायदे

एलोवेरा जेल में विटामिन-ए, विटामिन-सी और विटामिन-बी होता है जो कि स्किन को भरपूर मात्रा में पोषण देता है।
इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करता है।
एलोवेरा जेल में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण त्वचा को हर तरह के स्किन इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है।

स्किन रैशेज के लिए मुल्तानी मिट्टी

स्किन ब्राइटनिंग के लिए मुल्तानी मिट्टी बेहद असरदार होती है। मुल्तानी मिट्टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व त्वचा के ऊपर मौजूद टैनिंग को हटाने में मदद करते हैं।
त्वचा को डीप क्लीन करने के लिए मुल्तानी मिट्टी बेहद असरदार साबित होता है।

त्वचा को विटामिन-ई के फायदे

विटामिन-ई त्वचा में मौजूद सेल्स को जीवनदान देने में मदद करता है।
स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए विटामिन-ई बेहद काम में आता है।

स्किन रैशेज को कम करने का घरेलू उपाय

स्किन रैशेज को कम करने के लिए आपको सबसे पहले एक बाउल में एलोवेरा की पत्तियों में से जेल को निकालना होगा।
इसके बाद इसमें आप करीब 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और 1 विटामिन-ई के कैप्सूल को काटकर डाल सकती हैं।
इन तीनों को मिक्स करने के बाद आप स्किन रैशेज पर लगा सकती हैं।
करीब 15 से 20 मीनट तक इसे लगा रहने दें और फिर पानी और कॉटन की मदद से इसे साफ कर लें।
अब आप नार्मल स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर सकती हैं।
इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल आप हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार तक कर सकती हैं।

जीतना है पति और सासू मां का प्यार

तो पहनें इस तरह की साड़ियां

जब भी किसी लड़की की शादी पक्की होती है तो उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। सबसे बड़ी उलझन होती है कि आखिर वो कैसे ससुराल जाकर अपने पति और अन्य घर वालों का दिल जीतेगी। घर वालों में सबसे ज्यादा सासु मां का दिल जीतने के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ती है। वैसे तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी का भी दिल जीतने के लिए उसे उसके मन का अच्छा खाना खिलाना चाहिए। ये बात सच भी है लेकिन क्या आप जानती हैं कि एक और ऐसा तरीका भी है, जिसे अपनाकर आप अपने पति और सासु मां का दिल जीत सकती हैं। दरअसल, शादी के बाद अगर आप अलग-अलग तरीके की साड़ियां पहनेंगी तो सबका दिल जीतने में कामयाब हो जाएंगी। आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं कि शादी के कुछ दिन बाद तक आप कैसे तैयार हों और कैसी साड़ी पहनें।

बनारसी साड़ी

बनारसी साड़ी का अपना एक अलग ही अंदाज होता है। अगर इसे आप शादी के बाद पहनेंगी तो आपको देखकर आपके पति तो खुश हो ही जाएंगे, साथ में सासू मां भी आपकी तारीफ करती नहीं थकेंगी।

पूजा में पहनें लाल या पीला रंग

शादी के बाद कई दिनों तक रस्में चलती रहती हैं। ऐसे में अगर आपके ससुराल में कोई पूजा है तो सूट पहनने की बजाए लाल या पीले रंग की साड़ी पहनें। इसे पहनकर आप सबका दिल जीत सकती हैं।

डिजाइनर साड़ी

अगर आपकी शादी के बाद कुछ ही दिनों में घर में कोई और कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें डिजाइनर साड़ी पहनकर अपना जलवा दिखाएं।

चुन सकती हैं सिक्किन साड़ी

अगर आप कहीं पार्टी में जा रही हैं तो सिक्किन वर्क की साड़ी आपके लुक को पूरा करेगी। ये देखने में काफी अलग लगती है।

मेकअप का रखें ध्यान

साड़ी पहनते वक्त अपने मेकअप का खास ध्यान रखें। मेकअप करते वक्त ध्यान रखें कि ये ज्यादा ओवर ना हो। नई दुल्हनों पर मेकअप अच्छा तो लगता है लेकिन ओवर मेकअप उनका लुक बिगाड़ सकता है। मेकअप करते वक्त सिंदूर लगाना ना भूलें वो आपके लुक में चार चांद लगाएगा।

फर्स्ट डेट पर दिखना है स्मार्ट और डैशिंग तो प्लस साइज के लोग इन बातों का रखें ख्याल

हर लड़के की ख्वाइश होती है कि वो अपनी फर्स्ट डेट पर स्मार्ट लगे और लड़की को पहली बार में ही पसंद आ जाए। ये प्लस साइज वाले लड़कों के साथ भी होता है। प्लस साइज लड़के भी स्मार्ट और डैशिंग होते हैं, लेकिन उनको अपने लुक को और इनहैंस करने के लिए अपने अंदर थोड़े से बादलाव लाने पड़ेंगे। क्योंकि प्लस साइज लड़को को अपनी पहली डेट पर जानें के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे वो और ज्यादा गुड लुकिंग हों। यहां हम पर हम प्लस साइज मुंडो को अपनी फर्स्ट डेट पर जाने के लिए कुछ टिप्स दे रहे हैं, जिनकों अपनाकर वो अपनी डेट को पहली बार में ही इंप्रेस कर लेंगे।

रॉन्ग अटायर

सबसे अहम है आपका रॉन्ग अटायर, जो आपके पूरे लुक का सत्यानाश कर सकता है। इसलिए प्लस साइज लोग डेट पर जानें से पहले अपने आउटफिट पर ध्यान दे। प्लस साइज लोगों को फिट कपड़े ना पहन कर ढीले कपड़े सेलेक्ट करने चाहिए। इससे आप मोटे नहीं नजर आएंगे। डेट पर जाने से पहले ढीले कपड़े पहनें।

टीशर्ट के ऊपर चेक शर्ट पहनें प्लस साइज वाले पुरुषों को डेट पर जाने के लिए अपने आउटफिट में राउंड नेक टी शर्ट पहन सकते हैं। इसके साथ ही वो ऊपर से एक शर्ट डाल सकते हैं, शर्ट चेक हो तो ज्यादा अच्छी है, वैसे डेनिम की शर्ट भी चल सकती है। आप शर्ट को खुला रहे, जिससे आपका लुक उभर कर सामने आएगा और आप मोटे भी नहीं लगेंगे। हील शू को अवॉइड करें प्लस साइस लड़के अपने आउटफिट के साथ हील शू को ना पहनें, इससे उनके जूते बिल्कुल अलग ही नजर आएंगे, इसके साथ ही आपकी बॉडी के साथ सेट नहीं बैठते हुए दिखाई देते हैं, इससे आपको डेट का बार बार आपके जूतों पर जाएगा। इसलिए नॉर्मल हील के जूते पहने, साथ ही फॉर्मल शू पहनेंगे तो लुक आपका शानदार लगेगा।

इस तरह की जीन्स और पैंट ऑवाइड करें

आपको अपनी पैंट और जींस का सेलेक्शन भी करना होगा। अगर पैंट पहननी है तो पैटर्न वाली पैंट को पहनें जिससे आपके पैर हैवी ना नजर आए। वहीं अगर जींस पहन रहे हैं तो बिल्कुल स्किन टाइट जीन्स को ना पहने, ये आपके मोटापे को और ज्यादा दिखाएगी। एंकल लेंथ जींस आप पर खूब फबेगी।

नगरीय निकाय को स्कीम लागू करने का मिलेगा अधिकार

मंत्री का महापौर को फ्री हैंड, फायदे में लाएं एआइसीटीएसएल की बसें

विजयवर्गीय ने कहा- एक्सपर्ट ही करें बसों का संचालन

इंदौर। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी निकायों के महापौर और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। विजयवर्गीय ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव से कहा, एआइसीटीएसएल का संचालन एक्सपर्ट से कराएं ताकि योजना मुनाफे की साबित हो। फिलहाल एआइसीटीएसएल घाटे में चलने की बातें सामने आती रही हैं। अब तक इसका संचालन अफसरों के भरोसे ही किया जाता रहा है। एक्सपर्ट से संचालन कराने के लिए नगर निगम पूरी तरह स्वतंत्र है। इसके बाद यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इनका संचालन निजी हाथों में दिया जा सकता है, जिसके जरिए निगम को मुनाफा हो सके। बैठक में इसमें 16 नगर निगम के महापौर, निगम आयुक्त सहित अन्य अफसर शामिल हुए। बैठक में इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने निगम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आमजन को राहत देने सहित कई मुद्दों को उठाया तो मंत्री ने निकाय व शहरहित के कामों पर सहमति दे दी।

इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई चर्चा

शहर लगातार बढ़ रहा है। कुछ समय में अधिकारी-कर्मचारी रिटायर हुए हैं। रिक्त स्थानों पर भर्ती की आवश्यकता है। इसलिए इस दिशा में भी निर्देश दिए जाएं। बैठक में महापौर की इस मांग को शामिल किया, जिस पर सहमति आनी बाकी है।

नगरीय निकाय की स्कीम लागू करने के अधिकार के संबंध में विभाग ने एक खाका तैयार किया है। इसके तहत निगम स्वयं अपनी स्कीम बनाकर लागू कर सकता है। इसके अधिकार को स्वीकृति दी जाए। मालूम हो, अब तक इंदौर विकास प्राधिकरण ही अपनी योजनाएं विकसित करता है। इसको लेकर स्मार्ट सिटी को नोडल बनाए जाने को लेकर एक प्रपोजल भी शासन को भेजा गया है। जल्द ही इसको लेकर आदेश शासन स्तर से जारी हो सकता है।

महापौर ने कहा, लीज रिन्यूअल और फ्री होल्ड संबंधित अधिकार निर्देश जारी किए जाएं ताकि लीज आयुक्त को है। इस विषय में संबंधित, फ्री होल्ड और रिन्यूअल कार्य संकल्प द्वारा किए जा सकें।

आत्मनिर्भर निगम बनाने के लिए बैठक

भार्गव के मुताबिक, बैठक की शुरुआत में इंदौर में हुए वृहद पौधरोपण को आदर्श मानकर उसकी जमकर तारीफ हुई। बैठक का इसका उद्देश्य ही यही था कि कैसे आत्मनिर्भर निगम के तौर पर काम किया जाए।

सभी निकायों में एक जैसा काम और शहरहित प्राथमिकता में रखकर काम हो सके। कार्यों में लेटलतीफी न हो, इसलिए विभागीय मंत्री और अफसरों के सामने योजना बताकर उसकी हाथोहाथ स्वीकृति मिल सके।

इंदौर में बड़ी ठगी-

पीतल की ज्वेलरी पर चढ़ाई सोने की परत, गिरवी रखकर ले गए सवा दो करोड़ रुपये

इंदौर। बिजली विभाग के रिटायर्ड अफसर को ज्वेलर्स ने सवा दो करोड़ रुपये की चपत लगा दी। आरोपितों ने सोने की परत चढ़े पीतल के आभूषण गिरवी रखे और करोड़ों रुपये ले लिए। पुलिस ने एक आरोपित को हिरासत में ले लिया है। ठगी का आंकड़ा बढ़ सकता है। नकली आभूषण जब्त कर लिए हैं। विजयनगर टीआई सीबी सिंह के मुताबिक स्कीम-54 निवासी दिनेश चंद्र चोपड़ा ने शिकायत दर्ज करवाई है। दिनेश बिजली विभाग से रिटायर हुए हैं। उनकी पत्नी शिक्षा विभाग में पदस्थ रही हैं। 76 वर्षीय चोपड़ा सोना गिरवी रख कर ऋण देते थे।

शुरुआत में कम सोना गिरवी रख विश्वास जीता-वर्ष 2014 में वीणा नगर निवासी दीपक राधाशरण अग्रवाल संपर्क में आया। दीपक की परदेशीपुरा में अन्नपूर्णा ज्वेलर्स के नाम से सोना चांदी की दुकान है। शुरुआत में दीपक ने कम मात्रा में सोना गिरवी रखा और रुपये लिए। दिनेश उस पर विश्वास करने लगे और सोना की जांच करवाना बंद कर दी। दीपक और उसकी पत्नी महिमा ज्यादा मात्रा में सोना रखने लगे। दोनों के बीच लाखों रुपये का लेनदेन होने लगा। वर्ष 2022 में दीपक का भाई अरुण अग्रवाल भी सोना गिरवी रख कर रुपये लेने का काम करने लगा।

ब्याज के लालच में रिश्तेदारों से रुपये लेकर देने लगे-दिनेश ब्याज के लालच में रिश्तेदारों से रुपये लेकर आरोपितों को देने लगे। बदले में सोने के आभूषण गिरवी रखने लगे। 16 फरवरी को दिनेश ने रजत ज्वेलर्स से सोने की जांच करवाई तो ज्वेलर्स ने बताया आभूषण नकली हैं।

पुलिस ने हिरासत में लिया

आरोपित अब तक 94 बार में करीब सवा दो करोड़ रुपये ले जा चुके थे। दोनों पक्षों ने बैठक की तो आरोपितों ने नकली आभूषण गिरवी रखना स्वीकार लिया। दिनेश ने उनका वीडियो बना लिया। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली। रुपये न लौटाने पर डीसीपी जोन-2 अभिनय विश्वकर्मा को शिकायत की और शनिवार को एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने दिनेश को हिरासत में ले लिया है।

एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर में 6 वर्षों में 100 बोन मैरो का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट हुआ

इन्दौर। इंदौर का महात्मा गांधी स्मृति मेडिकल कॉलेज प्रदेश का एकमात्र ऐसा शासकीय चिकित्सा संस्थान बन गया है जहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की सफलता के 6 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है। इन 6 वर्षों में यहाँ के चिकित्सकों द्वारा 100 रक्त जनित बीमारी के मरीजों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हुये सफलतापूर्वक इलाज किया है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर द्वारा वर्ष 2018 में रक्त जनित कैंसर एवं रक्त जनित अन्य बीमारियों के इलाज हेतु बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी उच्च स्तरीय इलाज की सेवा शुरू की गई थी । मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित और सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर सुमित शुक्ला ने बताया है कि यहाँ 4 मार्च 2018 को पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया था । अब तक 100 रक्त जनित बीमारी के मरीजों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर इलाज किया गया। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सा संस्थानों में सिर्फ इंदौर एमजीएम मेडिकल कॉलेज ही एकमात्र चिकित्सा संस्थान है, जहां इस तरह की उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर की इस उपलब्धि पर सहयोगी संस्थाओं एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए 25 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय इंदौर में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम मुख्य अतिथि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विशेष अतिथि जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट एवं सांसद शंकर लालवानी, विधायक गोलू शुक्ला, महापौर पुष्यमित्र भार्गव की उपस्थिति में सम्पन्न होगा। कार्यक्रम में एम्स नई दिल्ली से डॉ. तुलीका सेठ भी उपस्थित रहेंगी

तीन राशन दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड

इंदौर। खाद्य विभाग ने 19 शासकीय उचित मूल्य दुकानों की आकस्मिक जांच की। गड़बड़ियां मिलने पर दो दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। तीन दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए, 16 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। जांच में पाया कि इन दुकानों द्वारा खाद्य सामाग्री की प्राप्ति दो-तीन सप्ताह के बाद ली जा रही है। स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर त्रिदेव प्रा. सह. उप. भंडार, समता प्रा.सह.उप. भंडार तथा भक्ति प्रिया महिला प्रा.सह.उप. भंडार के प्राधिकार निलंबित किए गए। गंभीर अनियमितताएं पर त्रिदेव प्रा.सह.उप. भंडार द्वारा संचालित दुकान के विक्रेता विनय जांगिड़ एवं समता प्रा.सह.उप. भंडार द्वारा संचालित दुकान के विक्रेता गोपेश्वर नागवंशी के विरुद्ध संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई।

इंदौर जिले के जोखिम भरे और एकान्त क्षेत्रों में जनसामान्य का प्रवेश प्रतिबंधित, आदेश के उल्लंघन पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

इन्दौर। जन सामान्य के जीवन की सुरक्षा को देखते हुये तथा हादसों की रोकथाम के लिए इंदौर जिले के जोखिम भरे और एकान्त क्षेत्रों में जन सामान्य के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार महू तहसील क्षेत्रों में स्थित तिंछा फॉल, चोरल फॉल, चोरल डेम, सीतलामाता फॉल, कजलीगढ, मेहन्दी कुण्ड, जामन्या कुण्ड आदि पर्यटन स्थलों पर जोखिम भरे क्षेत्रों व एकान्त क्षेत्रों में जन सामान्य के प्रवेश को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद द्वारा तत्काल उनके क्षेत्र में आने वाले पर्यटन क्षेत्र के आवश्यक स्थानों पर इस आशय के सूचना बोर्ड भी लगाये जायेंगे।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी जयश्री जैन द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स 13, प्रेस कॉम्प्लेक्स ए.बी. रोड इंदौर से मुद्रित एवं 22, प्रेस काम्पलेक्स, प्रेस हाऊस, ए.बी. रोड इंदौर 452008 से प्रकाशित। प्रधान संपादक- डॉ. राजेश जैन, मो. 9425322301 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)